मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 57 जनवरी, 2012 अंक 1

27 दिसंबर, 2011 को डॉ. पंजाबराव देशमुख के जन्मदिवस पर भारत कृषक समाज द्वारा श्रृद्धांजलि अर्पित

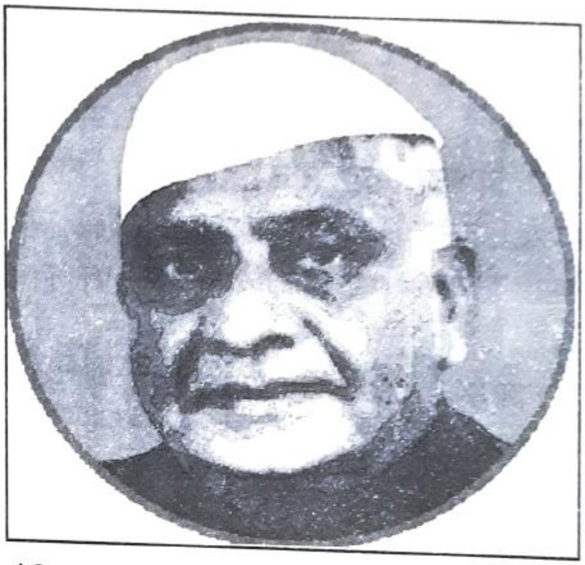

इस वर्ष 27 दिसंबर, 2011 को स्वर्गीय डॉ. पंजाबराव एस. देशमुख का 113वां जन्मदिन देशभर में भारत कृषक समाज की सभी शाखाओं द्वारा मनाया गया। इस दिन सभी किसानों और समाज के आजीवन सदस्यों को यह स्मरण होना चाहिए कि किसानों के प्रिय नेता डॉ. देशमुख ने ही सन् 1955 में किसानों की इस राष्ट्रीय संस्था – 'भारत कृषक समाज' की स्थापना 3 अप्रैल को की थी।

बैठकों, गोष्ठियों, सेमिनार व छोटे–छोटे जलसे देशभर में आयोजित कर डॉ. देशमुख का जन्म दिन मनाया गया। 27 दिसंबर, 2011 को भारत कृषक समाज के सभी जिलों व राज्य कार्यालयों में स्व. डॉ. देशमुख के जन्म दिन पर सभाएं आयोजित की गई जिनमें उनके चित्र को माल्यापर्ण की गई तथा उनके पुनीत व किसान सेवा के कार्यकलापों का स्मरण किया गया।

डॉ. देशमुख ने अपने जीवन में महात्मा गाँधी, नेहरू तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान लोगों के आदर्शों को अपनाया और उन्हीं महापुरूषों के पद्चिन्ह पर चलकर उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी संस्था भारत कृषक समाज की स्थापना की, जिसके आज लगभग एक लाख से अधिक सदस्य हैं। डॉ. देशमुख ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तब हमारे देश में किसानों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। डॉ. देशमुख ने भारत कृषक समाज के अंतर्गत किसानों को संगठित किया। डॉ. देशमुख खुद भी एक किसान थे इसलिए वह किसानों की परेशानियों से भली–भांति परिचित थे। उन्होंने सबसे पहले किसानों की नई पिढ़ी को शिक्षित करने पर जोर दिया ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। डॉ. देशमुख ने इंग्लैंड़ से शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी वकालत पूरी करने के बाद वह जनहित की सेवा में जुट गऐ, और महाराष्ट्र के छोटे से जिले अमरावती से उठकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषी मंत्री मनोनित हुए।

आज डॉ. पंजाबराव देशमुख जी के 113 वें जन्मदिवस पर हम उनके सपनों को साकार करने की प्रतिज्ञा लेते हैं।

– अजय जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

मिल्क ग्रिड़ को जोड़ना

भारत में छोटी–छोटी डेयरी

भारत में दूध, विशेष रूप से देश के अनेक शाकाहारी लोगों के लिए हमेशा से प्रोटीन एक महत्वपूर्ण स्रोत्र रहा है लेकिन भारत व यूरोप में हमेशा देध का प्रयाप्त उत्पादन नहीं हुआ जिससे की उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके। वर्ष 1950 तथा 1960 में भारत ने दूध की अत्याधिक कमी का सामना किया है तथा यह दूध के आयात पर निर्भर रहा है। लाखों भारतीय किसानों ने थोड़ी बहुत गायों को पालकर दूध का उत्पादन अवश्य किया है लेकिन वे किसी भी प्रकार से तेजी से बढ़ते हुए शहरों के लिए, जहां दूध की मांग बहुत अधिक बढ़ रही थी, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे।

गुजरात में डेयरी सहकारी संघ की सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड़ (एनडीडीबी) की सीापना की है तथा पूरे भारत वर्ष में गुजरात के आणंद जिले में सीापित डेयरी सहकारी समितियों के पैर्टन पर इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है। एनडीडीबी ने इस पर विचार किया तथा श्वेत क्रांति का कार्यक्रम तैयार किया जिसके तहत सहकारी समितियों में डेयरी किसानों को संगठित किया गया तथा दूध का और अधिक उत्पादन करने में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराया गया तथा छोटे डेयरी मालिकों के सहयोग से पर्यावरण नीति को लागू किया।

इससे राष्ट्रीय 'मिल्क ग्रिड़' का सजृन करने में सहायता मिली जिससे देश की डेयरी सहकारी समितियों की एक श्रृंखला को प्रमुख शहरों से जोडा गया ताकि दूध उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग तथा विपणन का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अंतर्गत, छोटे स्तर के डेयरी किसानों, ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं तथा भूमिहीन दूध उत्पादकों को शामिल किया गया है। पोषण में सुधार करने व गरीबी कम करने में इसका योगदान सफल रहा।

इनसे आज तीन गुणा उत्पादन हो गया है। भारत वर्ष भैंस तथा बकरी के दूध का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बडा उत्पादक देश है तथा गाय के दूध का उत्पादन करने वाला विश्व में छठे स्थान पर है। श्वेत कांति ने भारत में इस प्रकार से दुग्ध उत्पादन में कांति ला दी, जिस प्रकार से हरित कांति ने फसलों के उत्पादन में कांति दिलाई।

भारत में दूध की नदियां

यहां दूध का उत्पादन छोटे किसानों द्वारा किया जाता है जिनमें भूमिहीन कशषि मजदूर शामिल हैं जो मुख्य रूप से मजदूर परिवारों से हैं तथा वे दूध इकट्ठा करके

उपभोक्ताओं एवं बाजारों में पहुंचाते हैं। 80 प्रतिशत दूध तो केवल 2 से 5 गाय पालने वाले किसानों से आता है। इनमें से अनेक छोटे पशुपालक परम्परागत रूप से बाजार तक नहीं पहुंच पाते। अभी तक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध को इकट्‌ठा करके इसे पैक किया जा सके क्योंकि वह कार्य थोड़ा कठिन है और इसका परिवहन करना अधिक खर्चीला है।

गुजरात राज्य में आणंद जिले के दूध उत्पादकों ने इकट्‌ठा होकर अपने आपको एक निजी सहकारी समिति के रूप में संगठित किया जिसे 'कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड' के नाम से जाना गया। इस सहकारी समिति को देखने के पश्चात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह निश्चय किया की इस मॉडल को पूरे भारत वर्ष में दोहराया जाए। श्वेत कांति एक राष्ट्रीय स्तर का संघीय रूप से प्रायोजित एक कार्यकम है जो 1970 में आरंभ हुआ तथा 1996 तक चला।

श्वेत कांति दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था कि ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं तक इसकी सुनिश्चित आपूर्ति की जा सके तथा दूध उत्पादकों की आय में वश्द्धि हो सके।

ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क, जिला एवं क्षेत्रीय सहकारी संघ एवं राज्य विपणन महासंघों को राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड़ के नाम से जाना गया। डेयरी उद्योग के विभिन्न घटकों उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन को 3 चरणों में ध्यानपूर्वक बांटा गया है।

चरण–1 1970 से 1980 तक था में 4 मुख्य शहरी बाजारों में लक्ष्य में रखा गया था मुम्बई, कोलकता, दिल्ली तथा चैन्नई। (श्वेत कांति के समय इन्हें कमशः बम्बई, कोलकता, दिल्ली तथा मदरास के नाम से जाना जाता था) तथा इसमें 10 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शामिल किया गया था जिसमें कुल 1.8 मिलियन दुधारू पशुओं को शामिल किया गया था।

1981 से 1985 के बीच दूसरे चरण में इस कार्यकम को 10 मिलियन ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों तक बढ़ाया गया जिसमें लाखों उन्नत प्रजातियों व संकर जाति की गायों को शामिल किया गया।

इस चरण के दौरान, मिल्क शैडस की संख्या 18 से बढ़कव 27 की गई तथा विपणन कार्य का भारत के 144 प्रमुख शहरों तक विस्तार किया गया। तीसरा चरण, 1990 के बीच तक चला जिसमें इन कार्यों को समेकित करना तथा इस ग्रिड़ की शेष कमी को पूरा करने पर ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत लगभग 7 मिलियन कशषक परिवारों को शामिल किया गया तथा 170 मिल्क शेडस का प्रावधान किया गया तथा पशुओं के स्वास्थय संबंधी उन्नत तकनीकों को अपनाया गया।

भारत सरकार ने वर्ष 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया जिसे डेयरी सहकारी समितियों का मूल्यांकन, संर्वधन तथा उन्हें सहयोग करने का दायित्व सौंपा गया। देश में डेयरी के विकास को दिशा देने के लिए एनडीडीबी की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत प्लानिंग, किसानों को विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना तथा डेयरी प्रौद्योगिकीयों, पशु–चिकित्सा सेवाओं तथा पौषकता में सुधार के उपाय किये गऐ। एनडीबीबी के संस्थापक डॉ वरगीस कुरियन, अमूल के महाप्रबंधक ने सहकारी समितियों के एक स्वपन को वास्तविकता में परिर्वतित किया तथा श्वेत कांति के लिए समग्र डिजाइन तैयार किया।

श्वेत कांति के लिए वित्तिय व्यवस्था नऐ तरीकों से की गई। जब यूरोपियन इकॉनोमिक कम्यूनिटी (ईईसी) ने सरप्लस डेयरी उत्पादों – सकिम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर ऑयल की भारत में निशुल्क आपूर्ति की, श्वेत कांति के शिलपियों ने ईईसी की इन निशुल्क आपूर्तियों को भारतीय सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित दूध के साथ शामिल कर तथा डेयरी उद्योग के विकास के लिए, उसे लाभ पहुंचाने में सहयोग करने हेतु इन उत्पादों की सम्मिलित बिकी की गई। इस प्रकार, इस खाद्य सहायता से स्थानीय उत्पादन को सहयोग करने के लिए मुद्रा अर्जित की गई। इस इंटरवेंशन ने विश्व बैंक से ऋण भी प्राप्त किया।

श्वेत कांति ने डेयरी उद्योग का रूप कैसे लिया

श्वेत कांति, डेयरी सहकारी समितियों, रेफरिजरेटिड वैनों, रेलवे वैगनों तथा प्रोसेसिंग प्लांटों उत्पादन को खपत से जोडने के माध्यम से ग्रामीण डेयरी उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोडा। श्वेत कांति ने विभिन्न प्रकार की तकनीकी तथा डेयरी संबंधी आधुनिक इन्फास्ट्रक्चर शुरू करके इस प्रकिया में मदद की। उत्पादन की दृष्टि से, नये विकास में गायों की देशी नस्लों को संकर नस्ल में बदलना शामिल है जिससे की दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

अनुमानित आंकडें दर्शाते हैं कि एक देशी गाय प्रतिदिन लगभग 1.5 किलोग्राम दूध देती है, जबकि संकर नस्ल की गाय पदमितदव 4 किलोग्राम दूध देती है। प्रोसेसिंग के मामले में, आधुनिक कार्यों में साईलोज, पाश्चराईज, भंडारण टैंक तथा रेफरीजरेटर भी हैं जिससे दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तु को स्टोर करके राष्ट्रव्यापी स्तर पर बेचा जा सके। विपणन के मामले में, नई प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है ताकि दूध के माप–तौल तथा जांच कार्य में सुधार किया जा सके तथा इसकी बल्क बिकी की क्षमता बढ़ाई जा सके।

वस्तुतः संकर नस्ल तैयार करना भारतीय पशुओं की जानी–मानी नस्लों को लुप्त किऐ बिना भारत में दूध उत्पादकता में सुधार करना भारत सरकार की रणनीती का एक हिस्सा है। श्वेत कांति की रणनीति का केवल एक छोटा हिस्सा ही संकर नस्ल

के पशुओं पर केन्द्रीत है। यहां तक कि भूमिहीन दुग्ध उत्पादक भी कभी–कभी इन जानवरों को खरीदते हैं। वर्ष 1088–89 तथा 1995–96 की अवधि के बीच दूध उत्पादन 42 मिलियन लीटर प्रति दिन से बढ़कर 35 मिलियन लीटर प्रति दिन हो गई। एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि सामुदायिक स्तर पर श्वेत क्रांति से फायदा हुआ है।

यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि गांवों में परिवारों ने सहकारी समितियों के साथ मिलकर अपनी सभी आय के स्रोत्रों से औसतन अधिक आय अर्जित की, दूध की औसत आय बढ़ी तथा रोजगार के औसत स्तर भी बढ़े।

राष्ट्रीय मिल्क ग्रीड़ के सृजन से पूरे भारत में जिला संघों के बनने से रोजगार के अनेक अवसर बढ़े हैं; 21वीं सदी के आरंभ में 11 मिलियन परिवार डेयरी सहकारी समितियों में नियोजित थे।

यद्यपि, भारत में डेयरी क्षेत्र श्वेत क्रांति के बावजूद आगे बढ़ सकता था। श्वेत क्रांति के अर्न्तगत सहकारी समितियों का ढांचा अभी भी केवल देश में उत्पादित कुल दूध के बहुत कम भाग की खरीद तथा मार्केटिंग करता है। ये सहकारी समितियां औपचारिक, संगठित डेयरी क्षेत्र के एक प्रमुख हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ अन्य विकास घटकों की मदद से श्वेत क्रांति देश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहा है।

<u>दूरगामी प्रभाव</u>

श्वेत क्रांति की समाप्ति के पश्चात एक दशक से के बाद भी डेयरी सहकारी नेटवर्क ने निरन्तर प्रगति की तथा उत्पादन व विपणन के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ोत्री हुई। सहकारी समितियों में भागीदारों की संख्या बहुत अधिक रही है (2008 में 13 मिलियन जिनमें 3.7 मिलियन महिलाएं) तथा सहकारी समितियां अभी भी अत्यधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर रही हैं।

आज उपभोक्ताओं में दूध उत्पादों की बेहतर क्वालिटी के प्रति जागृति बढ़ी है। 1970 से लेकर दूध तथा दूध के उत्पादों में तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। 1970 तथा 2001 के बीच डेयरी उत्पादन लगभग 4.5 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़े है।

वर्ष 2007–2008 के सरकारी आंकडे दर्शाते हैं कि भारत एक वर्ष में 100 मिलियन टन से अधिक डेयरी उत्पादों का उत्पादन कर रहा है तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 250 ग्राम प्रतिदिन है जो श्वेत क्रांति के आरंभ होने से पहले 1980 में 180 ग्राम प्रतिदिन तथा 1968 में 113 ग्राम प्रतिदिन थी। डेयरी किसानों के बीच 1988–89 तथा 1995–96 के बीच दूध की प्रति व्यक्ति समग्र खपत 290

ग्राम से बढकर 339 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

श्वेत कांति के कारण भारत में दूध उत्पादकों की आय बढाने में भी अनुकूल प्रभाव पडा है। यद्यपि इस कार्यकम का मुख्य उद्देश्य आय के वितरण में सुधार लाना नहीं था बल्कि छोटे, सीमान्त किसान, भूमिहिन दुग्ध उत्पादकों व सभी व्यक्तियों तक पहुंचाकर दूध बाजार, संतुलित पशु आहार, पशुओं के स्वास्थय की देखभाल तथा कत्रिम गर्भधान (आर्टिफिसियल इनसेमिनेशन) सेवाओं द्वारा दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है। इस इंटरवेंशन से अमीर तथा गरीबों के बीच आय के वितरण पर अनुकूल प्रभाव पडेगा।

श्वेत कांति के अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि इस कार्यकम को ग्रामीण गरीबों में प्रभावशाली रूप से लागू किया गया। 1984 में 72 प्रतिशत सहकारी समितियां छोटे तथा सीमांत किसानों (अथवा वे जो 5 एकड़ जमीन से कम के मालिक हैं) के लिए चलाये गये हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित रूप से दूध इकट्ठा करने के पश्चात भूमिहिन किसानों की आय दोगुनी हो गयी।

प्रर्वति अध्ययनों से यह पता चला है कि भूमिहिन परिवारों की बीच उनकी आय बढाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा इस बात की पुष्टि हुई है कि दूध् ा उत्पादन के माध्यम से गरीब परिवारों की आय में बढोतरी हुई है।

श्वेत कांति से महिलाओं को भी लाभ पहुंचा है। महिला कामगारों सहित रोजगार की दर में श्वेत कांति बेनेफिशरीज के बीच नॉन बेनेफिशरीज की तुलना में बढोत्तरी हुई है। सहकारी समितियों में महिलाओं की न केवल दूध इकट्ठा करने में उनकी संख्या बढ रही है बल्कि वे अधिक मूल्यों, बेहतर जानकारी तथा अपने पशुओं के स्वास्थय के लिए उन्नत टैक्नोलॉजी का भी लाभ उठा रही हैं।

अब 25 प्रतिशत से अधिक महिलाएं सहकारी समितियों की सदस्य हैं तथा 2700 से अधिक महिला सहकारी समितियां कार्य कर रही है। महिलाओं को डेयरी सहकारी समितियों को चलाने में अपनी यह भूमिका निरन्तर निभानी होगी। तथापि 3 प्रतिशत से भी कम महिलाएं निदेशक मंडल की सदस्य हैं।

श्वेत कांति मॉडल से सीख

भारत में श्वेत कांति मॉडल को अन्य उत्पादों, खाद्य तेलों, फलों तथा सब्जियों के क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। एशिया के देश जैसे चीन, फिलिपाइन्स तथा श्रीलंका के लोग भी इस मॉडल को अपना रहे है। श्वेत कांति के डिजाइन तथा कार्यावयन के लिहाज से अनुकरणीय है तथा एक सशक्त माध्यम है जिससे ग्रामीण लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

खाद्य सहायता का इस्तेमाल विकास के लिऐ

खाद्य सहायता का इस्तेमाल परम्परागत रूप से तथा मुख्य रूप से प्राणी मात्र के इस्तेमाल के लिए। श्वेत क्रांति में पहली बार यह देखा गया कि खाद्य सहायता निवेश के लिए एक सशक्त संसाधन है।

श्वेत क्रांति के अंतर्गत यूरोपियन इकॉनोमी कम्युनिटी द्वारा खाद्य सहायता के रूप में भेजे गये डेयरी उत्पादों का कच्चे आदानों के रूप में इस्तेमाल किया गया और डेयरी विकास को वित्त पोषित करने के लिए प्राप्त होने वाली राशी का इस्तेमाल डेयरी सप्लाई चेन के विकास के लिए किया जा सका।

स्थानीय बाजार में निवेश

श्वेत क्रांति का लक्ष्य न केवल दूध उत्पादन में तेजी लाना था बल्कि दूध के लिए एक मजबूत विपणन ढांचा भी विकसित करना था। श्वेत क्रांति के शिलपियों ने पशुधन उत्पादों के लिए बढती हुई मांग का विशलेषण किया तथा इस मांग को पूरा करने के लिए एक एकीकृत तथा वृहद कार्यक्रम तैयार किया जो सप्लाई चेन, मैनेजमेंट सिस्टम एवं केन्द्रीकृत गुणवत्ता नियन्त्रण युक्त था।

श्वेत क्रांति ने यह प्रर्दशित किया है कि किसानों के बीच वाणिजियक सोच को बढाने में सामूहिक प्रयास एक प्रभावशाली साधन बन सकता है विकास प्रक्रिया ने अपने दायित्व को समझने में रूचि दिखाई।

सृजनातमक संरचना की पहल

श्वेत क्रांति से यह क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि डेयरी की शुरूआत कैसे हुई तथा इसे कैसे संगठित किया गया। एकल बुनियादी उत्पाद पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए इसने आरंभिक उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखते हुए इसने वर्टिकल इंटिग्रेटिड वैल्यू चेन का सृजन किया।

हॉरिजंटल इंटीग्रेशन – आदानों, विस्तार तथा सेवाएं एक ही कार्यक्रम के भीतर लाना। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली की इसके आर्थिक लाभ प्रत्येक उत्पादक को मिल रहे हैं। सहकारी तंत्र ने उत्पादकों के लिए यह आसान बना दिया कि वे नये उत्पादों तथा प्रक्रियाओं का कैसे इस्तेमाल किया जाए।

सारांश

श्वेत क्रांति भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। दुग्ध उत्पादन को बढाने की प्रौद्योगिकीयों के इस्तेमाल द्वारा और अधिक प्रभावी तथा कुशल आपूर्ति चेन स्थापित करके और उत्पादकों को बाजारों की ओर अभिमुख करके श्वेत क्रांति ने भारतीय डेयरी उद्योग का उत्तरोतर विकास करने में सहायता की। आज दुग्ध उत्पादन भारत वर्ष में एक बहुत बडा व्यापार है।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं०
U (C) 92/2009-11
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली-01, तारीख 4 एवं 5, जनवरी 2012

2007 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है तथा देश की सकल घरेलू उत्पाद में चावल से अधिक योगदान है।

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था में कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा दुग्ध उत्पादन का है तथा लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी दुग्ध उत्पादन के कार्य में लगी हुई है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

नव वर्ष 2012 की हार्दिक शुभकामनाऐं

भारत कृषक समाज की ओर से अपने सभी सदस्यगणों, शुभ चिन्तकों तथा कृषक समाचार के पाठकों को नव वर्ष की ढ़ेर सारी शुभकामनाऐं और समाज आशा करता है कि नव वर्ष 2012 आप सभी के जीवन में खुशहाली लाऐगा तथा हमारे किसान भाइयों को समृद्ध बनाऐगा।

– अजय जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज अपने सदस्यों के विवरण को अधतन करने की प्रक्रिया में हैं। सदस्यों को अपना पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई–मेल आई.डी. यदि हो तो महासचिव, भारत कृषक समाज, ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013 के पते पर भेजना आवश्यक है।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–46121708, 65650384, ई–मेलः contact@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।